THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) In his report on the subject, Director, Centre for Advanced Technology, Indorc has not envisaged any prima facie security risk to the said Centre because of the proposed establishment of the Diamond Park at Rangwasa in Indore District but has suggested a review of this issue by Security Officers of the Department of Atomic Energy. No team of the Department has so far visited Indore for this purpose. Before the visit of this Department's team, copies of orders of the High Court and Supreme Court in respect of the petitions concerning land acquisition proceedings for the proposed diamond park also need to be gone into.

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता

1915. **श्री गोविन्दराम मिरीः** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता कितनी है तथा अब तक इसका कितना उपयोग किया गया है;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का चालू वर्ष तथा आगामी तीन वर्षों में उपयोग करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का उचित ढंग से दोहन करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता के बारे में राज्यवार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन/विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कदम उठा रही है। इनमें अन्यों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना, अल्कोहलयुक्त पेयों के किण्वन व आसवन चीनी और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकतर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना, राजकोषीय सहायता प्रदान करना, घरेलू, विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। यह मंत्रालय कई योजना स्कीमें भी चला रहा है जिनमें राज्य सरकार के संगठनों/सहकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि को खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा विस्तार, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज के विकास, विपणन समर्थन, सूअर मांस, पॉल्ट्री, मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, मछली प्रसंस्करण, कोल्ड चेन की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास तथा कतिपय क्षेत्रों में जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है।

खाद्य उत्पादों के निर्यात के राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। फिर भी, देश से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात प्रतिवर्ष 18% से 20% की अधिकतम दर पर बढ़ रहा है और इस प्रवृत्ति के बने रहने की आशा है।

इन स्कीमों का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों समेत पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का सम्पूर्ण विकास करना है।

Setting up of Power Plants in Orissa and Andhra Pradesh

1916. SHRI K. M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any organisation in private sector prppsocs to set up a 250 MW power plant in the eastern coastal area of Orissa.

(b) if so, the details thereof, together with the progress made in this regard;

(c) whether Government propose to ask the said organisation to set up similar Power Plants in the coastal areas of Andhra Pradesh in near future; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?